names of the members of the committee are given in the attached statement. (*See* below)

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Statement

NAMES OF THE MEMBERS OF THE BIPARTITE COMMITTEE ON THE NEW INDUSTRIAL RELATIONS BILL

Chairman

Shri G. Ramanujam, President
Indian National Trade Union Congress.

Names of Members	*Organisation represented*
1. Shri Gopeshwar	Indian National Trade Union Congress
2. Shri Homi Daji	All India Trade Union Congress
3. Shri Umraomal Purohit	Hind Mazdoor Sabha
4. Shri Pritish Chanda	United Trade Union Centre (Lenin Sarani)
5. Shri G. Prabhakar	Bhartiya Mazdoor Sangh
6. Shri M. K. Pandhe	Centre of Indian Trade Unions
7. Shri P. D. Paliwal	Trade Union Coordination Centre
8. Shri N. M. Barot	National Labour Organisation
9. Shri Jatin Chakravorty	United trade Union Congress
10. Shri A. S. Kalsiwal	Council of Indian Employsrs
11. Shri M.R.R. Nair	Council of Indian Employers
12. Shri J. P. Chowdhary	Council of Indian Employers
13. Shri C.M. Krishna	Council of Indian Employers
14. Shri S. R. Grover	Council of Indian Employers
15. Shri B.P. Gupta	Council of Indian Employers
16. Shri I.P. Anand	Council of Indian Employers
17. Shri Ravi Bhoothalingam	Council of Indian Employers
18. Shri N.R. Patel	All India Manufacturers' Organisation.

नई श्रम नीति

1848. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम संगठनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने सरकार को नई श्रम नीति बनाये जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) राष्ट्रीय व्यवसाय संघ अभियान समिति ने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया था।

(ख) उक्त ज्ञापन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय व्यवसाय संघ अभियान समिति द्वारा अपने ज्ञापन में उठाए गए मामले

क्रमांक	ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे
1.	औद्योगिक संबंध विधेयक को वापिस लेना।
2.	लोक सभा में लंबित पड़े अस्पताल एवं अन्य संस्थान विधेयक को वापिस लेना।
3.	रक्षा उद्योग के कर्मचारियों को व्यवसाय संघ तथा प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान करना।
4.	एक केन्द्रीय कानून पेश करना जिसमें गुप्त मतदान द्वारा किसी यूनियन की मान्यता की व्यवस्था की गई हो।

5. 1982-100 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हटाना।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मंहगाई भत्ते संबंधी त्रिपक्षीय समिति आयोजित करना।

7. अधिकतम सीमा समाप्त करने के लिए बोनस अधिनियम में संशोधन।

8. कृषि श्रमिकों के बारे में एक केन्द्रीय विधान।

9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का सोपक्षेत्र बढ़ाना तथा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का क्रियान्वयन।

10. प्रवासी/बंधुआ श्रमिकों से संबन्धित कानूनी उपबन्धों को पूर्णतः लागू नहीं किया जा रहा है। उन्हें उचित रूप से लागू किया जाये तथा मौजूदा उपबन्धों को संशोधित किया जाय।

11. एसोसिएशन की स्वतन्त्रता तथा संगठित होने के अधिकार से संबंधित अं.श्र.स. अभिसमयों का अनुसमर्थन।

12. बन्द पड़े रुग्ण औद्योगिक एककों तथा औद्योगिक रुग्णता की इस समस्या से निपटने के लिए व्यवसाय संघों की एसोसिएशन को दोबारा शुरू किए जाने की आवश्यकता।

चावल, गेहूं और चीनी का आयात

1849. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल**: क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि भारत द्वारा इस वर्ष भारी मात्रा में चावल, गेहूं, और चीनी का आयात किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई पूर्वानुमान केन्द्रीय सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Action against hoarders of edible oils

1850. SHRI KAMAL MORARKA: *Will the Minister of* FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether any stringent action would be taken against those who are found guilty of increasing the edible oil prices illegally; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) and (b) All States/UTs have been requested to take stringent action against blackmarketeers, hoarders and anti-social elements under the essential Commodities act and other appropriate legislations, to arrest the rise in edible oil prices.

Allotment of Lands to Scheduled Castes in Badli village, Delhi

1851. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the Delhi Administration's Development Commissioner's circular No. F. 21(1)/P/82/5013—65 dated 28th June, 1982, the DDA (Delhi Development Authority) is refusing to hand back the land